भारत का महत्वाकांक्षी हाईवे विकास योजना

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगले 2 वर्षों में भारत 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा हाईवेज के ऊपर। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस स्टैंडर्ड के अनुरूप अपग्रेड करना।

इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का लक्ष्य है देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना और बॉर्डर तथा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज पर विशेष ध्यान देना, जिससे देश में आर्थिक विकास को गति मिल सके।

by OJAANK IAS

योजना के मुख्य उद्देश्य और सुधार

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण

देश के मौजूदा हाईवे नेटवर्क को रिबिल्ड और मॉडर्नाइज करके अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।

लेन विस्तार और सरफेस क्वालिटी

हाईवे की लेन विड्थ बढ़ाना और सरफेस की गुणवत्ता में सुधार करना जिससे यूएस स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जा सके।

सुरक्षा और प्रौद्योगिकी

रोड सेफ्टी मेजर्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन और ग्रीन एनर्जी का अधिक उपयोग।

इन सुधारों का उद्देश्य है भारतीय हाईवे को यूएस के एक्सप्रेसवेज के समान क्वालिटी, स्पीड और सेफ्टी के मामले में बनाना। साथ ही बॉर्डर एरियाज में डिफेंस लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

पूर्वी भारत पर विशेष फोकस

₹57,000 करोड़

आसाम

पूर्वोत्तर राज्य में हाईवे विकास के लिए निवेश

₹42,000 करोड़

पश्चिम बंगाल

बांग्लादेश सीमा के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए

₹53,000 करोड़

झारखंड

आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने हेतु

₹58,000 करोड़

उड़ीसा

तटीय राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए

इन पांच राज्यों (आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा) में कुल 3.7 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसमें 784 प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे और कुल 21,000 किलोमीटर हाईवे का विकास होगा। इन क्षेत्रों में मल्टीलेन हाईवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, बॉर्डर रोड्स और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत के हाईवे नेटवर्क में प्रगति

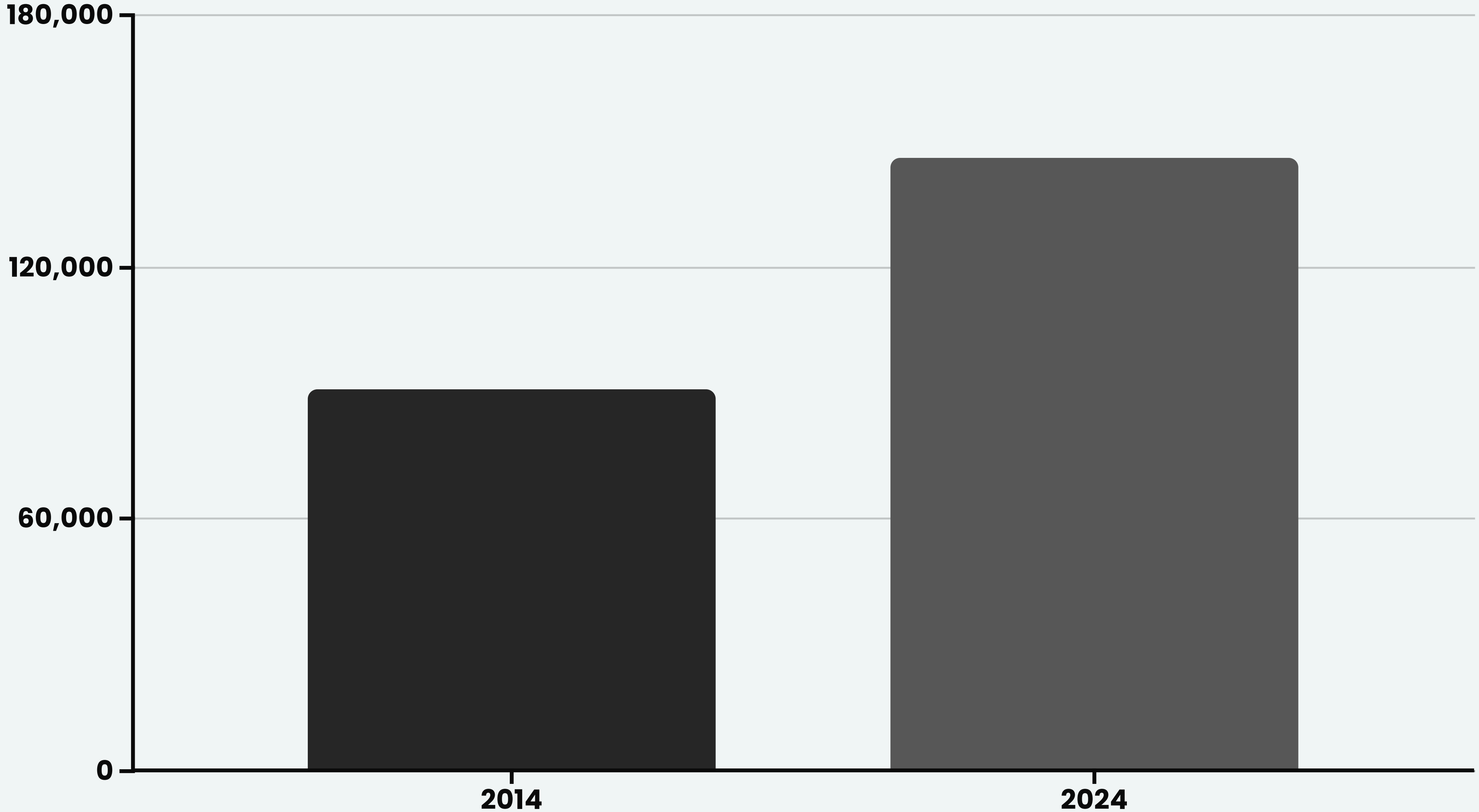

मोदी सरकार के आने से पहले 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 91,000 किमी थी। 2024 में यह 60% बढ़कर 146,000 किमी हो गई है, जो लगभग 1.5 लाख किमी है। इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दो लेन वाले हाईवे का प्रतिशत 30% से घटकर मात्र 9% रह गया है।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार लेन कैपेसिटी बढ़ाने, बॉटलनेक दूर करने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रयासरत है। अब अधिकांश हाईवे दो लेन से अधिक के बन रहे हैं, जिससे यातायात की गति और सुरक्षा में सुधार हो रहा है।

📞 कॉल करें - 8750711100/22/33/44/55 📲 8285894079

ग्रीन हाईवे और आधुनिक तकनीक

पर्यावरण अनुकूल पहल

- हाईवे के किनारे वृक्षारोपण
- सोलर लाइटिंग का व्यापक उपयोग
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

तकनीकी नवाचार

- फास्ट टैग सिस्टम का विस्तार
- सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन
- AI आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग

भौगोलिक चुनौतियों का समाधान

- पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक टनल निर्माण
- आधुनिक पुलों का निर्माण
- दुर्गम क्षेत्रों में विशेष इंजीनियरिंग समाधान

इस 10 लाख करोड़ के प्लान में पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) और हाइब्रिड एनुटी मॉडल (HAM) के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।

हाइब्रिड एनुटी मॉडल (HAM) का महत्व

सरकारी योगदान

40% फंडिंग सरकार द्वारा पांच चरणों में प्रदान की जाती है

निजी क्षेत्र का निवेश

60% फंडिंग निजी डेवलपर द्वारा जुटाई जाती है

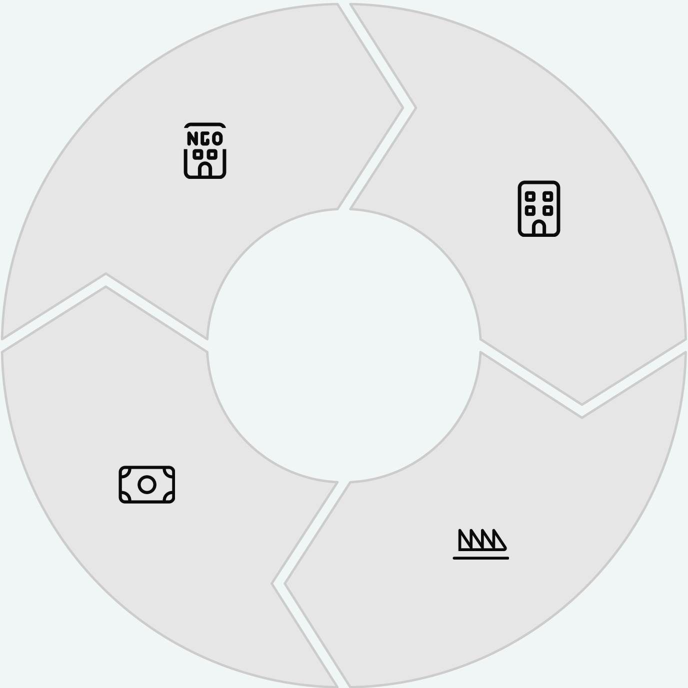

पुनर्भुगतान

15-20 वर्षों में सरकार द्वारा निजी निवेशक को एनुटी के रूप में भुगतान

निर्माण कार्य

निजी क्षेत्र द्वारा हाईवे का निर्माण और विकास

हाइब्रिड एनुटी मॉडल (HAM) 2016 में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, विशेष रूप से हाईवे डेवलपमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मॉडल में, निजी डेवलपर टोल कलेक्शन नहीं करता, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में एनुटी के रूप में भुगतान प्राप्त करता है।

यह मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जोखिम को संतुलित करता है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए हाईवे परियोजनाओं में निवेश करना अधिक आकर्षक बनता है। इस प्रकार, 10 लाख करोड़ के प्लान में HAM मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

राष्ट्रीय सुरक्षा

चीन, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करना।

लॉजिस्टिक्स सुधार

फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन देना और राज्यों के बीच माल परिवहन को सुगम बनाना।

पर्यटन विकास

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

रोजगार सृजन

निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना, जिससे देश की बेरोजगारी दर कम होगी।

इस विशाल हाईवे विकास योजना का रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्व है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगी, पर्यटन को विकसित करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

भविष्य के एक्सप्रेसवे और नवाचार

1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

आठ लेन का विशाल एक्सप्रेसवे जो अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह से खुल जाएगा।

2. अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे

1257 किमी लंबा कॉरिडोर जो पंजाब और गुजरात को जोड़ेगा।

3. गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 594 किमी का एक्सप्रेसवे।

4. इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्ट

नागपुर में 135 यात्री क्षमता वाली इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन बसों का पायलट प्रोजेक्ट।

भारत में कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-जामनगर, रायपुर-विशाखापटनम, वाराणसी-रांची-कोलकाता और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इनके अलावा, नितिन गडकरी जी ने नागपुर में इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्ट बस का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है।

यह पायलट प्रोजेक्ट 135 यात्रियों की क्षमता वाली गैर-प्रदूषणकारी बसों पर केंद्रित है, जो इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन ईंधन से चलेंगी। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा, जिससे शहरों के बीच तेज और पर्यावरण अनुकूल यात्रा संभव होगी।

👉 हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समान UPSC Special Current News PDF प्राप्त करें: www.ojaank.com

👉 दैनिक मुफ्त अंग्रेजी समाचार PDF लिंक:
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 दैनिक मुफ्त हिंदी समाचार PDF लिंक : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine